



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 दिसम्बर, 1990/29 अग्रहायण, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1990

संख्या 6-55/77-परिवहन-जिल्द-II.---मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बीच किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तिकारी करार का प्रारूप इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना तारीख 31-3-90 द्वारा तारीख 17-4-90 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था।

और इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और



संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बीच किए गए व्यक्तिकारी करार के प्रारूप को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
आर. एन. बंसल,  
आयुक्त एवं सचिव (परिवहन)।

लोक वाहन के लिये जम्मू कश्मीर, हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों के मध्य उत्तरी फ्री जोन पारस्परिक करार

यह करार आज उन्नीस सौ नवावी के/की.....के/.....दिन को पंजाब के राज्यपाल प्रथम पक्षकार, हरियाणा के राज्यपाल द्वितीय पक्षकार, जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल तीसरे पक्षकार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चतुर्थ पक्षकार और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये तथा उसकी ओर से भारत के राष्ट्रपति पांचवे पक्षकार के बीच तय पाया गया।

तारीख 22-7-1988 को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पक्षकारों के बीच हुये करार द्वारा उक्त पक्षकारों ने उक्त करार में दिये हुये निबन्धनों तथा शर्तों पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों द्वारा उनके बीच लम्बी दूरी के अन्तर्राज्य माल परिवहन को प्रोत्साहन देने के विचार से परस्पर करार किया था।

और उक्त करार 31 मार्च, 1982 को समाप्त हो गया था, आपसी करार द्वारा पक्षकार तारीख 22-7-1988 के उक्त करार में अन्तरविष्ट निबन्धों और शर्तों पर सहमत हो गये हैं और उन्होंने विद्यमान करार के आंशिक उपान्त्रण में इसमें यहां पर दिया गया करार करने का निश्चय किया है।

अतः उपयुक्त पक्षकारों में निम्नानुसार सहमति हो गई है :—

1. कि यह उत्तरी फ्री जोन करार प्रथम अप्रैल, 1989 से लागू होगा और 31 मार्च, 1991 तक विधिमान्य होगा।

2. इसे आगामी अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है, जिसके लिये उस करार के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा परस्पर सहमति हो।

3. परस्पर राज्यों के परिवहन प्राधिकारी अन्य राज्यों के क्षेत्रों के लिये विधिमान्य किसी भी संख्या में लोक वाहन अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

4. इस करार के अधीन चलाये जाने वाले लोक वाहन अपने राज्य के मार्गों पर बिना किसी पाबन्दी के चल सकेंगे जब कि अन्य राज्यों में किसी भी क्षेत्र में चलते समय परस्पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में समूच तौर पर अपने किन्हीं दो स्थानों के बीच से माल को न तो उठायेगा अथवा न ही उतारेगा अर्थात् ऐसी स्थिति में लोक वाहन को कोई अन्तर्राज्य व्यापार करने की मनाही होगी।

5. कोई भी वाहन इस करार के अधीन प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा। जो किसी भी समय पर वर्ष से अधिक पुराना हो।

6. इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहनों में निम्नलिखित दस्तावेज हर समय उपलब्ध रहेंगे.—

(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र।



(ख) योग्यता प्रमाण-पत्र

(ग) बीमा प्रमाण-पत्र ।

7. इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहनों की बाड़ी के बाई तथा दाई ओर सफेद रंग में वृत्तकार डिस्क बना रहेगा जिसका दायरा कम से कम 30 सेंटीमीटर का होगा और डिस्क पर काले रंग में फ्री जोन शब्द अंकित होंगे ।

8. परस्पर राज्य इस करार के अनुसार चलाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अपने राज्य के टोकन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, योग्यता प्रमाण-पत्र और बीमा प्रमाण-पत्र आदि को मान्यता देंगे ।

9. माल कर ऐसी दर पर देय होगा जो अपने राज्य में लागू हो और दूसरे राज्यों की उस दर पर देय होगा जो दर उस राज्य में प्रचलित हो । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में माल कर अपने राज्य द्वारा रेखित मांग ड्राफ्टों के माध्यम से अग्रिम रूप में वसूल किया जायेगा और अपने-अपने राज्यों द्वारा सम्बद्ध राज्य को भेज दिया जायेगा ।

10. सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्य द्वारा 63(1) के साथ पारित धारा 68(2) (डांडा) के अधीन यह उपबंधित करने के लिये उपयुक्त नियम बनायेगे कि इस प्रकार दिया गया संयुक्त अनुज्ञा पत्र दूसरे हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के क्षेत्रों में प्रतिहस्ताक्षरों के बिना विधि मान्य होगा ।

11. विशेष करार के अधीन जारी, प्राधिकार के अधीन चलने वाले वाहन को सहायक निरीक्षक मोटर वाहन या उप निरीक्षक पुलिस की पदवी के अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसकी पदवी से हस्ताक्षरकर्ता राज्य परस्पर सहमत हो इस करार के उपबन्धों को लागू करने के प्रयोजनों के लिये रोका जा सकता है । और इनका निरीक्षण किया जा सकता है । ऐसा निरीक्षण अधिकारी तीन प्रतियों में एक जांच रिपोर्ट करेगा जिसकी एक प्रति वाहन के कार्यभारी व्यक्ति को दी जायेगी और दूसरी प्रति अपने राज्य सक्षम परिवहन अधिकारी को भेजी जायेगी और तीसरी सम्बद्ध राज्य के सक्षम प्राधिकारी को भेजी जायेगी । जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर अपने राज्य का सक्षम अधिकारी परिवहन प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।

12. इस करार के प्रयोजन के लिये "वर्ष" शब्द को वित्त वर्ष समझा जायेगा ।

13. इस करार के प्रयोजन के लिये इनके पांच पक्षकारों में प्रत्येक पक्षकार के एक राज्य के रूप में समझा जायेगा ।

सचिव, पंजाब सरकार  
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ ।

( )  
सचिव, हरियाणा सरकार  
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ ।

( )  
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार  
परिवहन विभाग, शिमला ।

( )  
सचिव, जम्मू तथा कश्मीर,  
परिवहन विभाग, श्रीनगर ।

( )  
जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिये (और  
उसकी ओर से) सचिव, परिवहन  
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

(भारत के राष्ट्रपति के लिये और उसकी ओर से)



[Authoritative English text of this Government Notification No 6.55/77-Tpt. dated 22-10-1990 as required under Clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 22nd October, 1990*

No. 6-55/77-Tpt.-Vol-II.—Whereas in exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of the Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, a draft of the Reciprocal agreement proposed to be entered into by Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Delhi was issued *vide* this Department Notification of even number, dated 31-3-90 which was published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated 17-4-1990 inviting objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby, as required by Sub-Section (5) of the aforesaid Section.

And Whereas no objection/suggestion has been received from any person within the period specified for the purpose.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (6) of the Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish reciprocal agreement in the Himachal Pradesh Rajpatra entered into amongst the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Union Territory of Delhi.

By order,  
R. N. BANSAL,  
Commissioner-cum-Secretary (Tpt.).

North Free Zone Reciprocal Agreement for public carries between the States of Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Delhi

This Agreement made this.....day of One Thousand Nine Hundred and Eighty Nine between the Governor of Punjab of the First Part, the Governor of Haryana of the Second Part, the Governor of Jammu and Kashmir of the Third Part, the Governor of Himachal Pradesh of the Fourth Part and the President of India for and on behalf of the Union Territory of Delhi of the Fifth Part.

Whereas by an Agreement dated 22-7-1988, between the parties of the First, Second, Third, Fourth and Fifth Parts, the said parties entered into a reciprocal agreement with a view to encourage long distance inter-state Transport of goods by and between the State of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Delhi on the terms and conditions in the said Agreement contained.

And whereas the said Agreement expired on 31-3-1989.

And whereas by mutual Agreement, the parties hereto have agreed to the terms and conditions of the said agreement dated 22-7-1980 and have decided to enter into an Agreement as herein contained in partial modification of the existing Agreement.

It is now agreed between the above parties as follows :—

(i) That the North Free Zone Agreement shall come into force from the first day of April, 1989 and shall remain valid upto 31st March, 1991.



(ii) It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this Agreement.

(iii) The Transport Authorities of the reciprocating State shall issue any number of public carrier permits valid for the territory of the other States.

(iv) A public carrier operating under the Agreement shall be free to operate without restriction of routes in the some State where while operating in any area in the other states. It shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of reciprocal States i.e. in such case public carrier shall be prohibited from carrying on any inter-State business.

(v) No vehicle may be Authorised under this Agreement which is more than nine years at any point of time.

(vi) The public carriers playing under this Agreement shall at all times carry.

(a) Certificate of registration.

(b) Certificate of fitness.

(c) Certificate of Insurance.

(vi) The public carriers playing under this Agreement shall be painted on left and right side of the body with a white circular disc or not less than 30 cm in diameter with words "Free Zone" in back written on the disc.

(viii) The reciprocating States shall accord recognition to the token tax, registration certificate, certificate of fitness and certificate of insurance etc. of the Home State, in respect of vehicle plying in accordance with this Agreement.

(ix) The goods tax shall be payable at such rate as is applicable in the Home State and to the other States at the rate prevailing in that State. The goods tax shall be realised in advance by the Home State in respect of other States through crossed demand drafts and shall be remitted by the Home State to the concerned States.

(x) All the signatory States shall frame a suitable rule under Section 68 (2) (hh) road with Section 63 (i) to provide that the composite permit so granted shall be valid without counter-signature in the areas of the other signatory States.

(xi) A vehicle plying under authorisation issued under the Special Agreement may be stopped and inspected for the purpose of enforcement of the provisions of this Agreement by an officer of the rank of Assistant Inspector of Motor Vehicles or Sub-Inspector of Police or any other Officer whose rank is mutually agreed upon by the signatory States. Such an Inspecting Officer shall issue a check report in triplicate, one copy of which shall be served on the person incharge of the Vehicle, the second copy shall be sent to the competent transport authority of the Home State and the third copy sent to the competent transport authority of the Home State concerned. The competent transport authority of the Home State, on receipt of the check report may take action as he may deem fit.

(xii) For the purpose of this Agreement, the term year shall be deemed to be a financial year.



(xvii) For the purpose of this Agreement, each of the five parties hereto shall be deemed to be a State.

Sd/-

Secretary to the Govt. of  
Punjab, Transport Deptt.,  
Chandigarh, Governor For and  
On Behalf of Punjab.

Sd/-

Secretary to the Govt.  
of Haryana Transport Department,  
Chandigarh, For and On Behalf of  
Governor of Haryana.

Sd/-

Secretary Transport, Delhi  
Administration, Delhi,  
For and On Behalf of President  
of India.

Sd/-

Secretary to the Government of  
Jammu and Kashmir Transport  
Department Sqr.  
For and On Behalf of Governor  
of Jammu and Kashmir.

Sd/-

Secretary to the Government of Himachal  
Pradesh, Transport Department, Shimla.  
For and On Behalf of Governor  
of Himachal Pradesh.